

रैपिड रेल कॉरिडोर के लिये 16,000 करोड़ रुपए की मंजूरी

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार ने 16,000 करोड़ रुपए की रैपिड रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में कई हवाई अड्डों को नरिबाध रूप से जोड़ना है।

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परविहन नगिम (NCRTC) इस कॉरिडोर के लिये एक वसितृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जसि मार्च 2024 तक अंतमि रूप दयि जाने की उम्मीद है।

मुख्य बदि:

- एक बार शुरू होने के बाद, चार वर्ष के अनुमानति समापन समय के साथ यह परियोजनादो प्रमुख हवाई अड्डों और दलिली के वभिनिन हसिसों को जोड़ेगी।
- इससे आगामी नोएडा हवाई अड्डे को दलिली हवाई अड्डे से यात्री यातायात के अतपिरवाह को पकड़ने में सहायता मलिने की उम्मीद है।
- प्रस्तावति नोएडा हवाईअड्डा लकि गाज़ियाबाद स्टेशन से शुरू होगा, जो दलिली मेरठ रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट के लयि एकइंटरचेंज बदि के रूप में कार्य करेगा।
- यात्रियों के पास दलिली-मेरठ रेल के शुरुआती स्टेशन सराय काले खाँ के माध्यम से प्रगतरित दलिली-अलवर रैपिड रेल से जुड़ने का वकिल्प भी होगा।
- दलिली-अलवर रेल, वर्ष 2025 के मध्य तक समाप्त होने की उम्मीद है, इसमेंइंदरिा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और एयरोसिटी का स्टेशन शामिल होगा।
- नोएडा हवाई अड्डे के अधिकारी दलिली और गुडगाँव के साथ एक व्यापक मल्टी-मॉडल परविहन कनेक्टविटी नेटवरक स्थापति करने के लयि हाई-स्पीड बस कॉरिडोर सहति अन्य सार्वजनकि परविहन साधनों को वकिसति करने पर भी कार्य कर रहे हैं।